General Studies

Time Allowed : 3 Hours] **[Maximum Marks: 200]**
निर्धारित समय 3 घंटे] **[अधिकतम अंक 200]**

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS
प्रश्नपत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.
कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1.There are **TWENTY EIGHT** questions printed both in English and in Hindi.
कुल अठ्ठाइस प्रश्न दिए गए हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपे हुए हैं।

2.All questions are compulsory.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

3. Write answers in legible handwriting.
सुपाठ्य लिखावट में उत्तर लिखें।

4.Answer must be written in ENGLISH or HINDI.
उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में ही लिखे जाने चाहिये।

5. Keep the word limit indicated in the questions in mind.
प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिये।

6.Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
प्रश्न- सह उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग, जो खाली छोड़ा गया हो, उसे स्पष्ट रूप से काट दीजिये।

7.Re-evaluation / Re-checking of Question-cum-Answer Booklet of the candidate is not allowed.
अभ्यर्थी की प्रश्न-सह- उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच की अनुमति नहीं है।

Section-I/ खंड-I

Answer to question Nos. 1 to 15 should not exceed 60 words in each case. Contents of the answers are more important than their length. Each question carries 4 marks.
प्रश्न संख्या 1 से 15 के उत्तर प्रत्येक मामले में 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये। उत्तर की विषयवस्तु शब्द सीमा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं।

1. How does the Preamble influence the interpretation and development of the Constitution?
1. प्रस्तावना संविधान की व्याख्या और विकास को कैसे प्रभावित करती है?

2. Explain the concept of contempt of court and elucidate its constitutional provisions.
2. न्यायालय की अवमानना की अवधारणा की व्याख्या करें और इसके संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करें।

3. Why is there a need for establishment of various independent constitutional bodies in India?
3. भारत में विभिन्न स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता क्यों है?

4. Outline the procedural steps involved in initiating and passing a 'No-Confidence Motion' in the Indian Parliament and its impact.
4. भारतीय संसद में 'अविश्वास प्रस्ताव' शुरू करने और पारित करने में शामिल प्रक्रियात्मक कदमों और इसके प्रभाव रूपरेखित करें।

5. Examine the development and challenges related to reservation in promotions for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in public employment.
5. सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विकास और चुनौतियों की जांच करें।

6. Assess the limitations intrinsic to Fundamental Duties despite their critical role.
6. मौलिक कर्तव्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उनकी अंतर्निहित सीमाओं का मूल्यांकन करें।

7. How has the Collegium system for appointing and transferring judges evolved in India?
7. भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम प्रणाली कैसे विकसित हुई है?

8. How do Parliamentary committees help in keeping effective checks over the executive ?
8. संसदीय समितियाँ कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने में किस प्रकार सहायता करती हैं?

9. What are the challenges faced by Indian Federalism?
9. भारतीय संघवाद के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं?

10. Discuss the similarities and differences between judicial and quasi-judicial entities.
10. न्यायिक और अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के बीच समानताओं और अंतरों पर चर्चा करें।

11. What issues have caused people to lose trust and confidence in the Central Bureau of Investigation (CBI)?
11. किन मुद्दों के कारण लोगों का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर भरोसा कम हुआ है?

12. Discuss the major challenges faced by human rights institutions in India regarding their autonomy and propose viable solutions to enhance their statutory character.
12. भारत में मानवाधिकार संस्थानों की स्वायत्तता के संबंध में उनके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और उनके वैधानिक चरित्र को बढ़ाने के लिए व्यवहार्य समाधान प्रस्तावित करें।

13. Provide an analysis of the Socialist principles embedded within the Directive Principles of State Policy (DPSP) in the Indian Constitution.
13. भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के भीतर अंतर्निहित समाजवादी सिद्धांतों का विश्लेषण प्रदान करें।

14. How can giving an independent tribunal the power to decide on disqualification cases improve the effectiveness of the anti-defection law?
14. एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण को अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति देने से दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता में कैसे सुधार हो सकता है?

15. Evaluate the role of the Comptroller and Auditor General (CAG) in ensuring the accountability of the government in India.
15. भारत में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका का मूल्यांकन करें।

Section-II / खंड-II

Answer to question Nos. 16 to 25 should not exceed 120 words in each case. Contents of the answers are more important than their length. Each question carries 8 marks.
प्रश्न संख्या 16 से 25 के उत्तर प्रत्येक मामले में 120 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये। उत्तर की विषयवस्तु शब्द सीमा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न के 8 अंक हैं।

16. Outline the constitutional safeguards for the independence of Himachal Pradesh Public Service Commission and assess its effectiveness and limitations as a merit system watchdog in Himachal Pradesh.
16. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करें और हिमाचल प्रदेश में योग्यता प्रणाली प्रहरी के रूप में इसकी प्रभावशीलता और सीमाओं का आकलन करें।

17. Explain how Panchayati Raj institutions in India have evolved from focusing on 'Functions, Functionaries, and Funds' to now prioritising 'Functionality.' What are some key challenges they are currently facing regarding their functionality?
व्याख्या करें कि कैसे भारत में पंचायती राज संस्थाएं 'कार्य, कार्यप्रणाली और निधि' पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर अब 'कार्यक्षमता' को प्राथमिकता देने तक विकसित हुई हैं। वर्तमान में वे अपनी कार्यक्षमता के संबंध में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

18. Analyse how the Indian Constitution ensures the preservation of secularism, citing relevant Constitutional clauses.
18. प्रासंगिक संवैधानिक धाराओं का हवाला देते हुए विश्लेषण करें कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के संरक्षण को कैसे सुनिश्चित करता है।

19. Explain the eligibility criteria defined by NALSA for individuals to receive free legal aid and discuss its roles and functions.
19. व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा परिभाषित पात्रता मानदंडों की व्याख्या करें और इसकी भूमिकाओं और कार्यों पर चर्चा करें।

20. "In the landscape of justice, the writ stands tall as the beacon that guides the lost towards their inherent right."With this in mind, explain the nature and significance of writs under the Indian Constitution, incorporating relevant instances.
20. "न्याय के परिदृश्य में, रिट उस प्रकाशस्तंभ के रूप में खड़ी है जो खोए हुए लोगों को उनके अंतर्निहित अधिकार की ओर मार्गदर्शन करती है।" इसे ध्यान में रखते हुए, प्रासंगिक उदाहरणों को शामिल करते हुए, भारतीय संविधान के तहत रिट की प्रकृति और महत्व की व्याख्या करें।

21. What do you understand by the phrase "historical underpinnings of the Indian Constitution" and how did these historical underpinnings influence Constitution's development and progression?
21."भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार" वाक्यांश से आप क्या समझते हैं और इन ऐतिहासिक आधारों ने संविधान के विकास और प्रगति को कैसे प्रभावित किया?

22. Examine the arguments in favour of and against the implementation of the Uniform Civil Code (UCC) in India.
22. भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का परीक्षण करें।

23. Compare the legislative powers of the Rajya Sabha and the Lok Sabha according to the Constitution, and what unique powers are specifically granted to the Rajya Sabha?
23. संविधान के अनुसार राज्य सभा और लोकसभा की विधायी शक्तियों की तुलना करें और राज्य सभा को विशेष रूप से कौन सी अनन्य शक्तियाँ प्रदान की गई हैं?

24. Examine the key arguments both for and against the proposition of holding simultaneous elections for Parliament and State Assemblies in India.
24. भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों में प्रमुख तर्कों की जांच करें।

25. The concept of 'Basic Structure' , despite not being explicitly defined in the Indian Constitution, reflects a unique innovation within the Indian judicial system. Illuminate your answer by tracing its evolution through landmark judgments and its impact on constitutional amendments and governance in India."
25. 'बुनियादी संरचना' की अवधारणा, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होने के बावजूद, भारतीय न्यायिक प्रणाली के भीतर एक अद्वितीय नवाचार को दर्शाती है। ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से इसके विकास और भारत में संवैधानिक संशोधनों और शासन पर इसके प्रभाव का पता लगाकर अपने उत्तर पर प्रकाश डालें।"

Section-III / खंड-III

Answer to question Nos. 26 to 28 should not exceed 400 words in each case. Contents of the answers are more important than their length. Each question carries 20 marks.
प्रश्न संख्या 26 से 28 के उत्तर प्रत्येक मामले में 400 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये। उत्तर की विषयवस्तु शब्द सीमा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

26. "Provide a detailed analysis of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023, highlighting its historical background, main provisions, and the arguments in its favour and against it. Moreover, elucidate on its potential impact on women's representation in Indian politics."
26. "नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करें, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मुख्य प्रावधानों और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर प्रकाश डालें। इसके अलावा, भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर इसके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालें।"

27. While the Stamp of Presidential consent is crafted from a symbol-signing tool, the ink source it must engage before leaving an imprint is the utilisation of an unbiased intellect, deliberately positioned at the pinnacle of our Constitution's structure."
In the light of the above statement, is the constitutional position of the Indian President just equivalent to a rubber stamp?
27. जबकि राष्ट्रपति की सहमति की मोहर एक प्रतीक-हस्ताक्षर उपकरण से तैयार की जाती है, छाप छोड़ने से पहले इसे जिस स्याही स्रोत में शामिल करना चाहिए वह एक निष्पक्ष बुद्धि का उपयोग है, जो जानबूझकर हमारे संविधान की संरचना के शिखर पर स्थित है।
उपरोक्त कथन के आलोक में, क्या भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति रबर स्टाम्प के बराबर ही है?

28. Discuss the foundational role of Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950, and the Representation of the People Act 1951 in structuring and operationalizing the electoral process in India.
28. भारत में चुनावी प्रक्रिया की संरचना और संचालन में संविधान के अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की मूलभूत भूमिका पर चर्चा करें।